

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबोरेट्री को 'NABL मान्यता'
2.	राजस्थान के 72 स्थान 'हिल एरिया' और 'कठिन क्षेत्र' घोषित
3.	'अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता' में राजस्थान
4.	राजस्थान में साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख पहलें
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. 'जयपुर विमेन फेस्टिवल' के पहले चैप्टर की शुरुआत 2. राजेंद्र मोहन शर्मा की कहानी 'भीमा' को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार 3. इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट मॉडल 4. इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड - 2026 के विजेता
6.	सोमनाथ मंदिर
7.	महाराणा प्रताप की जयंती
8.	मिशन मौसम
9.	निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया
10.	त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका
11.	भारत की वृद्ध होती आबादी
12.	जननी (JANANI) प्लेटफॉर्म
13.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
14.	भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)
15.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)
16.	UN-हैबिटेट
17.	प्रोजेक्ट फ्रीडम
18.	INS सागरध्वनि
19.	विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026
20.	स्कूली शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट
21.	शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI)

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबोरेट्री को 'NABL मान्यता'

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI), दुर्गापुरा की पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबोरेट्री को 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (NABL) द्वारा मान्यता प्रदान की गई।



RARI, Durgapura
Rajasthan Agricultural Research Institute
Durgapura, Jaipur

Pesticide Residue Laboratory at

RARI, Durgapura

granted accreditation by the
**National Accreditation Board
for Testing and Calibration
Laboratories (NABL).**



Internationally
Recognized
Accreditation



Reliable
Testing



Accurate
Results



Ensuring Food
Safety and
Public Health

Commitment to Quality • Trust in Testing • Safety in Every Sample



मुख्य बिन्दु:

- मान्यता अवधि :** यह NABL मान्यता वर्ष 2030 तक के लिए प्रभावी रहेगी। इससे पूर्व वर्ष 2015 में भी इस प्रयोगशाला को NABL की मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



- **महत्त्व** : संस्थान की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी, साथ ही प्रदेश के किसानों, कृषि उद्यमियों एवं आमजन को भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
- उल्लेखनीय है कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेबोरेट्री श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की अधीनस्थ इकाई है, जो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI), दुर्गापुरा (जयपुर) में स्थित है।
- **उद्देश्य** : इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न, फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के अवशेषों (Pesticide Residues) की मात्रा की जाँच करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)

- राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) भारत का एक प्रमुख स्वायत्त निकाय है, जो प्रयोगशालाओं की तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है।
- यह केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) का एक प्रमुख घटक है।

--3--

राजस्थान के 72 स्थान 'हिल एरिया' और 'कठिन क्षेत्र' घोषित

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 मई, 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेश के 72 स्थानों को आधिकारिक तौर पर 'हिल एरिया' (पहाड़ी क्षेत्र) और 'कठिन क्षेत्र' (दुर्गम स्थान) घोषित किया है।



मुख्य बिन्दु:

- यह निर्णय द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों के अनुपालन में लिया गया है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य दुर्गम, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करना है।

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



- हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, माउंट आबू, कुंभलगढ़ और गोगुंदा को 'पर्वतीय क्षेत्र' घोषित किया गया है, जबकि अलवर, बाड़मेर, बाँसवाडा, जैसलमेर, करौली, उदयपुर और टोंक समेत 29 न्यायिक जिलों के 69 क्षेत्रों को 'कठिन स्थान' की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रमुख लाभ:

- **विशेष भत्ता** : इन 72 क्षेत्रों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को अब ₹5,000 प्रतिमाह का विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- **एरियर का भुगतान** : यह फैसला 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना गया है, जिसके फलस्वरूप अधिकारियों को 10 साल का एरियर (बकाया राशि) भी प्राप्त होगा।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--5--

'अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता' में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- 6 से 8 मई, 2026 तक MSEB होल्डिंग कंपनी द्वारा 'अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- आयोजन स्थल : श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे।
- राजस्थान का प्रतिनिधित्व : राजस्थान के विद्युत निगमों की कुल 6 टीमों के 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

--:6:--

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



राजस्थान का प्रदर्शन :

- **सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट** : राजस्थान के दल ने 'सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट' की ट्रॉफी जीती। मार्च पास्ट में राजस्थान के दल का नेतृत्व मैनेजर पवन शर्मा ने किया।
- **महिला खो-खो टीम** : पहली बार भाग ले रही राजस्थान की महिला खो-खो टीम ने रनर-अप (द्वितीय स्थान) ट्रॉफी जीती।
- फाइनल में महिला खो-खो टीम को महाराष्ट्र पावर टीम ने हराया।
- इस टीम की सभी खिलाड़ी सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की कनिष्ठ अभियंता (JENs) थीं।
- खो-खो टीम की कप्तान पूनम (JEN, सूरतगढ़ थर्मल) को बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड दिया गया।
- **पुरुष खो-खो टीम** : महाराष्ट्र पावर को हराकर तृतीय स्थान (कांस्य पदक) हासिल किया।
- **कुश्ती** : जयपुर डिस्कॉम के दीपक कुमार ने रजत पदक जीता।
- **नोट** : 13 से 15 मार्च, 2026 तक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोटा में '47वीं अखिल भारतीय विद्युत पॉवरलिफ्टिंग और बॉडीबिल्डिंग' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

--7:--

राजस्थान में साइबर सुरक्षा संबंधी प्रमुख पहलें

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्ष 2030 तक राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई।



राजस्थान सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर जायी की एडवाइजरी



- 'डिजिटल अरेस्ट' और कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से सतर्क रहने की अपील
- साइबर अपराध की स्थिति में नजदीकी पुलिस थाना या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं
- साइबर व्हाट्सएप नंबर (राजस्थान पुलिस) 9256001930 पर, 24 घंटे के भीतर करें रिपोर्ट



RajGovOfficial

--:8:--

मुख्य बिन्दु:

- साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तर पर साइबर अपराधों की निगरानी और रोकथाम के लिए एक विशेष 'राजस्थान साइबर कंट्रोल सेंटर' भी शुरू किए जाने की घोषणा की गई।
- साइबर सुरक्षा में राजस्थान का स्थान : ठगी गई राशि को फ्रीज करने और धोखाधड़ी नेटवर्क को तोड़ने के मामले में राजस्थान पुलिस देश में 5वें स्थान पर है।
- राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना : साइबर अपराध की नई चुनौतियों से बचाव के लिए राजस्थान में साइबर न्यायालय की स्थापना की जाएगी।
- राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर ठगी की रोकथाम के लिए संचालित ऑपरेशन : ऑपरेशन म्यूल अकाउंट एवं POS, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एंटी वायरस और ऑपरेशन वज्र प्रहार।
- राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर : 24 मई, 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 'राजस्थान के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर' की शुरुआत की गई। यह साइबर सपोर्ट सेंटर 'रेस्पॉन्सिबल नेटिज़न्स एवं कोग्टा फाउंडेशन' द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) : प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की तर्ज पर 'राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C)' की स्थापना की जाएगी।
- सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर : यह विश्वविद्यालय राज्य में साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के रूप में कार्य कर रहा है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़																
1.	<p>'जयपुर विमेन फेस्टिवल' के पहले चैप्टर की शुरुआत</p> <ul style="list-style-type: none">मदर्स डे (10 मई, 2026) के अवसर पर इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS) और खेल सेतु फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 'जयपुर विमेन फेस्टिवल' के पहले चैप्टर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जागरूकता, संवाद एवं प्रेरणा का मंच प्रदान करना था।																
2.	<p>राजेंद्र मोहन शर्मा की कहानी 'भीमा' को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जयपुर के वरिष्ठ साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा की कहानी 'भीमा' को 'सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानी' का पुरस्कार दिया गया।यह सम्मान धारवाड़ (कर्नाटक) की संस्था 'माटी के मानस' द्वारा प्रदान किया गया।																
3.	<p>इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट मॉडल</p> <ul style="list-style-type: none">राजस्थान सरकार पहली बार इंटीग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (IID) मॉडल के तहत प्रदेश के विकास की कार्ययोजना पर काम कर रही है।इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिक और शहरी बुनियादी ढाँचे को एक साथ जोड़कर समग्र विकास सुनिश्चित करना है।इस कार्ययोजना की शुरुआत जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र से की जा रही है।																
4.	<p>इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड - 2026 के विजेता</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जगतपुरा (जयपुर) स्थित गुप्त वृंदावन धाम द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड-2026' का परिणाम घोषित किया गया।इस प्रतियोगिता में जयपुर के डॉ. केवल कृष्ण गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 'गीता रत्न' का खिताब जीता। <table border="1"><thead><tr><th>स्थान</th><th>खिताब</th><th>विजेता का नाम</th><th>शहर</th></tr></thead><tbody><tr><td>प्रथम</td><td>गीता रत्न</td><td>डॉ. केवल कृष्ण गुप्ता</td><td>जयपुर</td></tr><tr><td>द्वितीय</td><td>गीता विभूषण</td><td>यशस्वी श्रृंगी</td><td>कोटा</td></tr><tr><td>तृतीय</td><td>गीता भूषण</td><td>नेहा महावर</td><td>कोटा</td></tr></tbody></table>	स्थान	खिताब	विजेता का नाम	शहर	प्रथम	गीता रत्न	डॉ. केवल कृष्ण गुप्ता	जयपुर	द्वितीय	गीता विभूषण	यशस्वी श्रृंगी	कोटा	तृतीय	गीता भूषण	नेहा महावर	कोटा
स्थान	खिताब	विजेता का नाम	शहर														
प्रथम	गीता रत्न	डॉ. केवल कृष्ण गुप्ता	जयपुर														
द्वितीय	गीता विभूषण	यशस्वी श्रृंगी	कोटा														
तृतीय	गीता भूषण	नेहा महावर	कोटा														

इतिहास एवं संस्कृति

सोमनाथ मंदिर

चर्चा में क्यों?

- सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थरों की याद में मनाया जाता है।



मुख्य बिन्दु:

- 1026 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए पहले दर्ज हमले के बाद से 1,000 वर्ष पूरे हो गए हैं।
- स्वतंत्रता के बाद मई, 1951 में मंदिर के पुनः खुलने के बाद से 75 वर्ष बीत चुके हैं।

सोमनाथ

- **स्थान** : गुजरात में सौराष्ट्र तट के किनारे स्थित प्रभास पाटन।
- **उत्पत्ति** : यह स्थल भगवान शिव और चंद्र देव की पूजा से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
- **विशेषताएँ** : सोमनाथ भगवान शिव के बारह आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला होने के कारण एक पवित्र स्थान रखता है।
- मंदिर परिसर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप शामिल हैं।
- मंदिर के शिखर पर 150 फुट ऊँचा शिखर है, जिसके ऊपर 10 टन का कलश स्थापित है।
- बिल्व पूजा जैसे अनुष्ठानों में प्रतिवर्ष 13.77 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं।
- **महत्त्व** : इसमें शिव पुराण में वर्णित सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है।
- यह स्थान भगवान शिव, भगवान कृष्ण और शक्ति की पूजा के लिए पूजनीय है।
- द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम् बारह ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को प्रथम स्थान पर रखता है
- **जीर्णोद्धार** : बार-बार विनाश होने के बावजूद, स्थानीय शासकों और भक्तों द्वारा मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया।
- कुमारपाल ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।
- जूनागढ़ के राजा ने तेरहवीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण कराया था।
- इंदौर की मराठा रानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने विनाश के बाद अठारहवीं शताब्दी में सोमनाथ में एक नए मंदिर की स्थापना का विकल्प चुना।
- **स्वतंत्रता के बाद की स्थिति**: सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 में सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया और मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया।
- वर्तमान मंदिर का निर्माण कैलाश महामेरु प्रसाद की स्थापत्य शैली में किया गया था।
- मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा कई बार नष्ट किए गए इस मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में किया गया और मई 1951 में यह कार्य पूरा हुआ। पुनर्निर्माण की देखरेख वल्लभभाई पटेल ने की थी।
- 11 मई, 1951 को राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का विधिवत अभिषेक किया गया।

वीर हमीरजी गोहिल

- वह एक क्षेत्रीय योद्धा थे और परंपरा में उन्हें जफर खान के आक्रमण के दौरान 1299 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है।

महाराणा प्रताप की जयंती



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।



मुख्य बिन्दु:

महाराणा प्रताप

- महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई, 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था।
- वह मेवाड़ के शासक, राजपूतों के सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे।
- **हल्दीघाटी का युद्ध (1576):** महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया।
- इससे निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई, क्योंकि महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद दक्षिणी मेवाड़ की पहाड़ियों में पीछे हटकर अपना प्रतिरोध जारी रखा।
- उनका घोड़ा चेतक भी अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है।
- **देवर का युद्ध (1582):** एक महत्वपूर्ण मोड़ जहां प्रताप की सेना ने एक विशाल मुगल सेना को निर्णायक रूप से हराया, जिससे उन्हें अपने अधिकांश क्षेत्र की पुनः प्राप्ति हुई।
- प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद कर्नल टॉड ने प्रताप को 'राजस्थान का लियोनिडास' की उपाधि दी थी।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

मिशन मौसम

चर्चा में क्यों?

- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में मिशन मौसम के तहत एक अत्याधुनिक 'अर्बन टेस्टबेड' और 'एरोसोल वेधशाला' स्थापित की है।



मुख्य बिन्दु:

मिशन मौसम:

- **शुरुआत:** 2024 में
- **मंत्रालय:** केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) और IITM

लक्ष्य:

- राष्ट्र को 'वेदर-रेडी' और 'क्लाइमेट स्मार्ट' बनाना।
- मौसम और जलवायु पूर्वानुमान सेवाओं में सुधार करना। यह कृषि, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास सहित कई क्षेत्रों के लिए समय पर और सटीक अवलोकन, मॉडलिंग और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी सुनिश्चित करता है।

--:14:--

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया



चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया 'निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंकुशता' है।



मुख्य बिन्दु:

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में CEC और ECs की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 324(2) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगी।
- **सांविधिक प्रावधान:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (जिसने 1991 के अधिनियम का स्थान लिया) उच्चतम न्यायालय के 2023 के अनूप बरनवाल वाद में दिए निर्णय के प्रत्युत्तर में लागू किया गया।
- इस निर्णय में आदेश दिया गया था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, तब तक CEC और ECs की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।
- **CEC और ECs की वर्तमान चयन प्रक्रिया में शामिल हैं:**
- **खोज समिति:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में यह समिति 5 योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करती है।
- **चयन समिति:** यह समिति राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश करती है।
- **चयन समिति में शामिल होते हैं:** प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता (या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता)।
- **पात्रता :** ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर रहे हों या वर्तमान में कार्यरत हों।

--:15:--

नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित चिंताएँ

- **कार्यपालिका का वर्चस्व:** चयन समिति में सरकार को 2:1 का बहुमत प्राप्त है (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री बनाम विपक्ष के नेता)।
- **खोज समिति की सिफारिश की उपेक्षा:** चयन समिति खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल की उपेक्षा कर "किसी भी अन्य व्यक्ति" को चुन सकती है।
- **रिक्तियों के बावजूद नियुक्तियाँ:** चयन समिति में सभी सदस्य नहीं होने पर भी नियुक्तियाँ करने की अनुमति है, जिससे सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व बढ़ सकता है।

अन्य चिंताएँ:

- **नौकरशाही का एकाधिकार:** केवल सचिव-स्तर के अधिकारी ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं;
- **दर्ज में गिरावट:** वेतन और सेवा शर्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के बजाय कैबिनेट सचिव के समकक्ष कर दिया गया है।

CEC और ECs की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन पर सुझाव

- **तारकुंडे समिति (1975), गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग (255वीं रिपोर्ट, 2015):** इन्होंने तीन सदस्यीय कॉलेजियम की सिफारिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों।
- **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002):** इसने एक ऐसे पैनल की सिफारिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हों।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की रिपोर्ट (2007):** इसने एक ऐसे कॉलेजियम की सिफारिश की जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री तथा राज्यसभा के उपसभापति शामिल हों।

त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु के 2026 के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा बनी, जिसमें टीवीके ने 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटों से कम 108 सीटें जीतीं।

मुख्य बिन्दु:

त्रिशंकु विधानसभा

- जब किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो विधानसभा को "त्रिशंकु" कहा जाता है। इससे गठबंधन वार्ता शुरू होती है और छोटी पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- राज्यपाल एक प्रमुख संवैधानिक अधिकारी के रूप में यह तय करने का कार्य करता है कि सरकार बनाने के लिए पहला निमंत्रण किसे मिलेगा।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 163:** राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ उसे विवेक का प्रयोग करना आवश्यक हो।
- **अनुच्छेद 164(1):** राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, वह दलों को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने में विवेकाधिकार का प्रयोग करता है।
- **अनुच्छेद 163(2):** यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी मामले में राज्यपाल के विवेक की आवश्यकता है, तो उनका निर्णय अंतिम होगा और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका

- इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए, राज्यपाल जनता का जनादेश प्राप्त दल को आमंत्रित करता है और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है।
- इसके बाद राज्यपाल नामित मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाने के लिए समय निर्धारित करते हैं।

- विधायकों को शपथ दिलाने और सदन में मतदान कराने के लिए एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो आमतौर पर निर्वाचित विधायकों में सबसे वरिष्ठ होता है।
- सदन में सदन का विश्वास मत जानने के लिए सदन परीक्षण (जिसे 'विश्वास मत' भी कहा जाता है) आयोजित किया जाता है। यह परीक्षण सदन के सदस्यों के बीच मतदान के माध्यम से किया जाता है।
- यदि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विधानसभा की मौजूदा संरचना के तहत कोई सरकार नहीं बन सकती, तो वे केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं।

राज्यपाल की भूमिका पर रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

- **सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1983):** इसमें कहा गया था कि यदि विधानसभा में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो उस पार्टी के नेता को स्वतः ही मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा जाना चाहिए।
- हालांकि, यदि ऐसी कोई पार्टी नहीं है, तो राज्यपाल को नीचे दिए गए क्रम में वरीयता के अनुसार निम्नलिखित पार्टियों में से एक मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए :
- चुनावों से पहले गठित दलों का एक गठबंधन ।
- सबसे बड़ी एकल पार्टी अन्य दलों, जिनमें "स्वतंत्र" उम्मीदवार भी शामिल हैं, के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रही है।
- चुनाव के बाद बनी पार्टियों की एक ऐसी गठबंधन सरकार, जिसमें गठबंधन के सभी सहयोगी शामिल होंगे।
- चुनाव के बाद दलों का एक गठबंधन बनता है, जिसमें गठबंधन में शामिल कुछ दल सरकार बनाते हैं और शेष दल, जिनमें "स्वतंत्र" दल भी शामिल हैं, सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं।

- **पुंछी आयोग (2007):** इसने व्यापक रूप से सरकारिया ढाँचे का समर्थन किया लेकिन यह भी कहा कि राज्यपालों को संवैधानिक तटस्थता के साथ कार्य करना चाहिए और राजनीतिक एजेंडों के रूप में नहीं।
- इसमें कहा गया है कि बहुमत का निर्धारण करने के लिए यथाशीघ्र एक फ्लोर टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, चुनाव पूर्व गठबंधनों को चुनाव पश्चात की व्यवस्थाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे एक स्पष्ट चुनावी जनादेश को दर्शाते हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट के फैसले:** एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यपाल को सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता, या सबसे बड़े दल/समूह के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
- 2006 में, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने समय से पहले विघटन के खिलाफ चेतावनी दी और इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
- 2016 में, उत्तराखंड में इसी तरह के संकट के मामले में भी, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को "अंतिम" विकल्प के रूप में रेखांकित किया था और तत्कालीन कांग्रेस मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।

समाजशास्त्र

भारत की वृद्ध होती आबादी

चर्चा में क्यों?

- UNFPA 2023 के अनुमान के अनुसार भारत की कुल आबादी में वृद्धजनों का अनुपात 2050 तक 20% (347 मिलियन) तक हो जाएगा, जो 2011 में 8.6% था।



मुख्य बिन्दु:

- वृद्धावस्था एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है तथा बीमारियों और मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।
- यह जीवन में होने वाले बदलावों; जैसे सेवानिवृत्ति, स्थान परिवर्तन और मित्रों या जीवनसाथी की मृत्यु/वियोग से भी जुड़ा होता है।

वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी चुनौतियाँ

- **अस्पताल-केंद्रित मॉडल:** मौजूदा प्रणालियों में एकल रोगों का उपचार होता है, जबकि वृद्धजन प्रायः कई दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जिनके लिए निरंतर और एकीकृत देखभाल की आवश्यकता होती है।

-:20:-

- **मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव:** प्रायः डिमेंशिया, अल्जाइमर और अवसाद जैसे रोगों का निदान नहीं हो पाता है।
- एकल परिवारों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता ने सामाजिक अलगाव और "एम्प्टी नेट सिंड्रोम" में वृद्धि की है।
- **वित्तीय असुरक्षा:** स्वास्थ्य पर जेब से किया जाने वाला अत्यधिक खर्च परिवारों को बार-बार गरीबी में ले जाता है।
- 78% वृद्धों को पेंशन नहीं मिलती है और 70% आर्थिक रूप से आश्रित हैं।
- **वृद्धावस्था का नारीकरण:** महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक है, लेकिन अक्सर उनके पास कम संपत्ति और स्वास्थ्य देखभाल तक कम पहुँच होती है।
- **अन्य:** वृद्धावस्था संबंधी प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, डिजिटल सुविधाओं की कमी, ग्रामीण-शहरी विभाजन आदि।

आगे की राह

- **दीर्घकालिक देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करना:** आवश्यक अवसंरचना और वित्तीय सहायता को शामिल करते हुए एकीकृत वृद्धजन-देखभाल प्रणाली विकसित की जाए।
- **डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करना:** आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत टेलीपरामर्श और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बढ़ावा देना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **आयुष्मान भारत - PMJAY:** 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार की सुविधा।
- **वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:** सुलभ, वहनीय और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल।
- **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल:** युवा उद्यमियों को विश्वसनीय वृद्धावस्था देखभाल समाधान विकसित करने और सिल्वर इकोनॉमी में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना:** आयु संबंधी दिव्यांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करती है।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

जननी (JANANI) प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जननी (JANANI - प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और नवजात शिशु के लिए एकीकृत देखभाल यात्रा) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।



मुख्य बिन्दु:

जननी (JANANI)

- यह प्रजनन आयु के दौरान महिलाओं के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यापक निगरानी और रखरखाव के लिए तैयार किया गया एक सेवा-उन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह मौजूदा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पोर्टल का एक उन्नत संस्करण है, जो देखभाल की निरंतरता में प्रमुख सेवा वितरण घटनाओं को दर्ज करके एक दीर्घकालिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- समन्वय:** यू-विन (U-WIN) और पोषण (POSHAN) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों को एकीकृत करता है।
- विशिष्ट पहचानकर्ता:** लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए आभा (ABHA), आधार (OTP और बायोमेट्रिक) और मोबाइल नंबर जैसी पहचानकर्ता सुविधाएँ।
- अन्य:** QR-आधारित डिजिटल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के लिए स्वचालित अलर्ट, पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड, आदि।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)



चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान मजबूत प्रदर्शन प्रदर्शित किया है।



मुख्य बिन्दु:

- **महिला लाभार्थी:** सूक्ष्म उद्यमों को दी गई कुल सहायता का लगभग 40% महिलाओं को प्राप्त हुआ है।
- **SC/ST/OBC श्रेणियाँ:** लगभग 54% लाभार्थी।
- **ग्रामीण:** PMEGP के तहत स्थापित लगभग 80% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।

PMEGP

- **संबंधित मंत्रालय:** केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) (KVIB, DIC और कॉयर बोर्ड के साथ)।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** बैंक ऋणों पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में संभावित उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है।
- **अनुमत अधिकतम परियोजना लागत:** विनिर्माण इकाई के लिए ₹50 लाख और सेवा इकाई के लिए ₹20 लाख है।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)

चर्चा में क्यों?

- भारत और यूरोपीय संघ ने 15.2 मिलियन यूरो की संयुक्त पहल शुरू की। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिकल वाहनों की बैटरियों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के वर्किंग ग्रुप-2 के तहत शुरू की गई है।



मुख्य बिन्दु:

- यह पहल यूरोपीय संघ के होराइजन यूरोप कार्यक्रम और भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित की जाएगी।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC):

- **प्रारंभ:** फरवरी, 2023
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य चीन पर यूरोपीय संघ की निर्भरता और रूस पर भारत की निर्भरता को कम करते हुए भारत और यूरोप को रणनीतिक स्वायत्तता की ओर ले जाने का प्रयास करना है।
- **तीन मुख्य कार्य समूह (WGs):**
 - **WG 1:** रणनीतिक प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल शासन और कनेक्टिविटी
 - **WG 2:** हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
 - **WG 3:** लचीली मूल्य श्रृंखलाएँ, व्यापार और निवेश

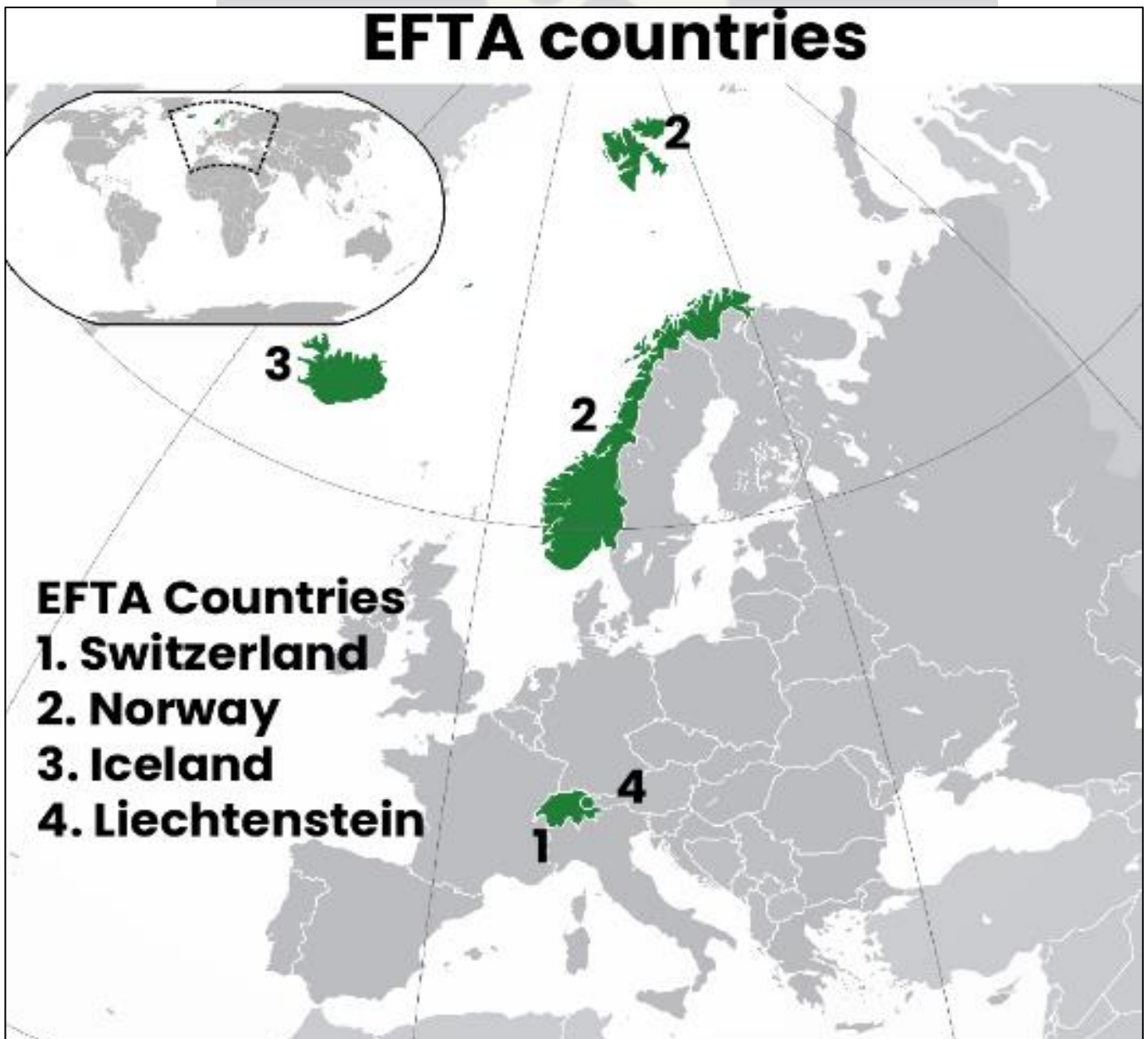
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)

चर्चा में क्यों?

- भारत के वाणिज्य सचिव भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं।

मुख्य बिन्दु:

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA):



--:25:--

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



- EFTA एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे 1960 में स्टॉकहोम अभिसमय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य:** आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
- **प्रारंभिक संस्थापक सदस्य:** ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम।
- भारत यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद EFTA का 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- EFTA देशों में, स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है।

--:26:--

UN-हैबिटेट



चर्चा में क्यों?

- UN-हैबिटेट ने 'कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस 2026-2029' लॉन्च किया है।



मुख्य बिन्दु:

- यह कैटलॉग सीधे UN-हैबिटेट रणनीतिक योजना 2026-2029 का समर्थन करता है, जिसे 2025 में अपनाया गया था।

UN-हैबिटेट:

- **स्थापना:** 1977 में, हैबिटेट I ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम (या UN-हैबिटेट) की नींव रखी।

- **अधिदेश:** सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना।

- **मुख्यालय:** नैरोबी (केन्या)।

जारी महत्वपूर्ण दस्तावेज:

- वैकूवर घोषणा-पत्र (हैबिटेट I),
- इस्तांबुल घोषणा-पत्र (हैबिटेट II),
- द न्यू अर्बन एजेंडा (हैबिटेट III - क्विटो, इक्वाडोर)।

--:27:--

प्रोजेक्ट फ्रीडम



चर्चा में क्यों?

- अमेरिका ने हाल ही में शुरू की गई अमेरिकी पहल 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' को स्थगित करने की घोषणा की है।



मुख्य बिन्दु:

- 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमले शुरू करने के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य काफी हद तक अवरुद्ध रहा है।
- ईरान ने जवाब में उस महत्वपूर्ण जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे होकर दुनिया के 20% तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस को निर्बाध रूप से गुजरना चाहिए।

Strait of Hormuz



--:28:--

Daily Current Affairs

Date : 11 May, 2026



- ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के कारण फंसे हजारों व्यापारिक जहाजों को मार्गदर्शन देने के लिए अमेरिका ने यह अभियान शुरू किया ।
- इस अभियान में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत, 100 से अधिक विमान और लगभग 15,000 कर्मी शामिल हैं जो चौबीसों घंटे सातों दिन सुरक्षा प्रदान करते हैं।



-:29:-

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

INS सागरध्वनि

📢 चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को रेखांकित करते हुए INS सागरध्वनि युद्धपोत वियतनाम पहुँचा।



📌 मुख्य बिन्दु:

- इसे सागर मैत्री (SM-5) पहल के 5वें संस्करण के लिए रवाना किया गया था।
- सागर मैत्री, भारतीय नौसेना और DRDO की एक प्रमुख सहयोगी पहल है। यह भारत के 'महासागर/MAHASAGAR (विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) विजन के अनुरूप है।

INS सागरध्वनि

- यह जुलाई, 1994 में कमीशन किया गया एक विशेष समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है।
- इसे DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन किया गया और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है।

--:30:--

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 जारी की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारत-यूएई और भारत-अमेरिका प्रवासन गलियारे 2024 में शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गलियारों में शामिल थे।



मुख्य बिन्दु:

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- 2024 में वैश्विक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 3.7% थी, जबकि 1990 में यह 2.9% थी।
- 2024 के मध्य तक लगभग 304 मिलियन लोग अपने जन्म देश से बाहर रह रहे थे।
- विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा मैक्सिको-संयुक्त राज्य अमेरिका गलियारा बना हुआ है, जिसमें लगभग 11 मिलियन प्रवासी हैं।

--:31:--

- अन्य प्रमुख गलियारों में शामिल हैं: अफगानिस्तान-ईरान गलियारा, सीरिया-तुर्की गलियारा और रूस-यूक्रेन गलियारा।

भारत-यूई प्रवासन गलियारा

- भारत-संयुक्त अरब अमीरात गलियारा विश्व स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा है।
- संयुक्त अरब अमीरात में 80 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी रहते हैं, जो इसकी कुल जनसंख्या का लगभग 74% हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिनकी संख्या 3 मिलियन से अधिक है।
- इस गलियारे में श्रम प्रवास का प्रभुत्व है, विशेष रूप से निर्माण, सेवा, परिवहन और घरेलू कामगार क्षेत्रों में।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासन गलियारा

- भारत-अमेरिका गलियारा विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा है। 2024 में लगभग 32 लाख भारतीय प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे।
- अमेरिका में रहने वाले विदेशी मूल के लोगों में मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय प्रवासी दूसरा सबसे बड़ा समूह हैं।

स्कूली शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के पिछले एक दशक का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।



मुख्य बिन्दु:

- इसमें शिक्षा तक पहुँच तथा नामांकन, अवसंरचना, समानता और सीखने के परिणाम जैसे पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

भारत में स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति

- व्यापक विस्तार:** 2024-25 में 14.71 लाख स्कूलों में 24.69 करोड़ विद्यार्थी पढ़ रहे थे।
- सकल नामांकन अनुपात (GER):** प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उच्च सकल नामांकन अनुपात (90.9%) है, लेकिन माध्यमिक (78.7%) और उच्चतर माध्यमिक (58.4%) स्तरों पर विद्यार्थियों की भागीदारी कम हो जाती है।
- निजीकरण की ओर झुकाव:** सरकारी स्कूलों में 49.25% विद्यार्थी नामांकित हैं, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त (प्राइवेट अनएडेड) स्कूलों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 38.8% कर ली है।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (GRAI)



चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के बीमा प्रभाग ने GRAI रैंकिंग में ग्रुप A श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि बैंकिंग प्रभाग ने मार्च, 2026 के लिए जारी रैंकिंग में लगातार दूसरे महीने 5वाँ स्थान बरकरार रखा है।



मुख्य बिन्दु:

GRAI

- **विकासकर्ता:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)।
- **उद्देश्य:** यह केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के माध्यम से शिकायत निवारण की प्रभावशीलता और समयबद्धता के आधार पर मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन करता है।
- CPGRAMS एक 24x7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदायगी से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **4 आयामों पर आधारित (11 संकेतक):** दक्षता, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता।